श्री राजनारायण : यानी, डिमोक्रेसी में यह आप अनुचित समझते हैं कि आप एक दल के किसी व्यक्ति का पैर तुड़वा दें . . .

श्री सभापति : तुड़वाया। क्या कह रहे हैं आप।

श्री राजनारायण : आपकी सरकार . . .

श्री सभापति मेरी सरकार क्या कर रही है. . .

श्री सभापति : अरे, आप उपराष्ट्रपति भी है। अगर राष्ट्रपति के खिलाफ पेटीशन खत्म न हो गय होता तो आप राष्ट्रपति हो गये होते।

श्री सभापति : अब आप बैठ जाइये। हो गई आपकी बात। कालिंग अटेन्शन मोशन।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आपका सचिवालय रो रहा है। आप घर विभाग को कहें एक विधेयक लाया जाये ताकि उनके लिये भी सुनिश्चित रूप से नियम की पाबंदी चले।

श्री सभापति : अच्छा। अब आप बैठ जाइये।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED STRIKE IN THE BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED HARDWAR

डा० भाई महावीर (दिल्ली) : श्रीमन्, में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार में हुई हड़ताल तथा उसके परिणामस्वरुप उत्पादन में भारी हानि होने के समाचार की और औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं।

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED) : Mr. Deputy Chairman, Sir, on the 22nd April, 1970, the Heavy Electrical Workers Trade Union of Heavy Electricals Limited submitted a list of 12 demands to the management and stated that if these demands were not fulfilled within 15 days, the Union would go on strike with effect from 7th May, 1970. Immediately on receipt of this notice, the Chairman, B.H.E.L., was asked to take immediate steps in the matter. The Chairman, B.H.E.L., took immediate steps for the Dy. Labour Commissioner initiating discussions at Hardwar and also contacted the State Government in the Labour Department to help the management in reaching a settlement with labour. According to the latest information, the strike commenced from the morning of 12th May, 1970, and is still continuing. The Chairman, B.H.E.L., has informed the concerned union through its President that detailed discussions on all the demands of labour could commence from 15th May, 1970, if the strike was called off. Despite this, it appears from the latest reports that the strike has not yet been called off. The strike has been declared illegal by the Deputy Labour Commissioner.

While the Union representatives had submitted a list of 12 demands consisting of various service matters and amenities, the most important demand appears to be regarding the continuance of Project Allowance on the basis of what was sanctioned prior to 1st April, 1969. Government policy in the matter of project allowance to public sector during the construction stage is that the allowance should compensate for lack of amenities such as schools, housing, markets, dispensaries during the construction stage and that this allowance should be tapered off in stages with the introduction of these amenities till it is finally withdrawn. This policy is being consistently followed in all the three constituent units of the B.H.E.L. The project allowance in the Tiruchi Boiler Plant of B.H.E.L. was withdrawn from 1st April, 1966, while in the Hyderabad Unit of B.H.E.L., the project allowance was discontinued with effect from 1st April, 1970.

The situationt in the Heavy Electrical Equipment Plant at Hardwar has substantially altered since the time when the unit was commenced and project allowance sanctioned. At present there is a

[Shri Fakhruddin Ali Ahmed]

full-fledged hospital with 75 beds, English and Hindi medium schools, water, electricity, markets, community centres, clubs, transport facilities and 2,300 quarters for workers. In view of these amenities, the Company has decided to reduce the project allowance gradually in consonance with the general policy laid down and in order to avoid undue hardship by its total withdrawal in one stage. The action is neither arbitrary nor is it designed to cause hardships to the workers. Any revision of the scale of project allowance which has now been decided would result in invidious discrimination in favour of the H.E.E.P. Unit of B.H.E.L. as against other units of the same concern. It may also be pointed out that as a result of recent agreement, the management has sanctioned a substantial increase in the pay scale of the workers.

The management have already shown its willingness to discuss the demands and it is hoped that the Union would respond in a positive manner. It is extremely unfortunate that this strike has taken place in this public sector unit. Any strike invariably involves considerable loss of production, particularly in an undertaking of this magnitude. It is essential that any differences between labour and management are settled in a spirit of tolerance and mutual goodwill. I would appeal to the labour to return to work as early as possible.

डा० भाई महावीर : श्रीमन्, मैं कुछ हैरान हूं, कुछ दुःखी हूं कि इस तरह की हड़ताल एऐसे एक महत्वपूर्ण संस्थान में क्यों हुई जो कि कुछ अर्से ही से अच्छा परिणाम दिखलाना शुरू करने लगी थी और खासकर उस समय पर यह हड़ताल की नौबत आई जब कि थोड़े समय पूर्व ही श्रमिकों का वेतनमान कुछ बढ़ाया गया था।

श्रीमन्, मैं वहां होकर आया हूं, कारखाना देखकर आया हूं और मुझे जनरल मैनेजर महोदय ने यह अवसर दिया कि मैं उनके साथ बैठ कर कुछ बात कर सकूं तथा उनका दृष्टिकोण समझ सकूं। महोदय, मैं यह बात समझ नहीं पाया हूं कि सरकार ने एक ऐसे सवाल को थोड़े धीरज से, थोड़ी उदारता के साथ क्यों नहीं सुलझा लिया और ऐसी परिस्थिति आने की नौबत सरकार ने क्यों पैदा की।

पहली बात यह है और मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस समय सदन का समाधान करायें कि 19 अप्रैल, 1969 से वहां के श्रमिकों को जो 20 प्रतिशत का प्रोजेक्ट एलाऊन्स मिलता था; उसको 15 प्रतिशत क्यों कर दिया। वहां के यूनियनों के लोगों ने इसके विरोध में एक आवेदन किया और वह आवेदन कंसिलिएशन आफिसर के पास ठीक तरह से हल न होने के बाद लेबर कमिश्नर के पास भेजा गया और लेबर कमिश्नर ने इसको सेण्ट्रल गवर्नमेंट के पास ट्राइब्यूनल के सामने भेजने का फैसला किया। ये जो टेक्नीकल स्टेजेज थीं वे चल रही थीं और वहां के श्रमिकों ने, वहां के मजदूरों ने यह समझा था कि ट्राइब्यूनल से उनको न्याय मिलेगा कि यह प्रोजेक्ट एलाऊन्स कम किया जाना चाहिये या नहीं और इसका फैसला न्यायिक आधार पर हो जायेगा। लेकिन 1-5-70 से यह प्रोजेक्ट एलाऊन्स घटा कर आधा कर दिया गया। जिन लोगों को अभी तक 15 परसेंट प्रोजेक्ट एलाऊन्स मिल रहा था उनको $7\frac{1}{2}$ परसेंट मिलने लगा और जिनको $7\frac{1}{2}$ परसेंट मिल रहा था उनको पौने चार परसेंट मिलने लगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आपने इस मामले को ट्राइब्यूनल के सामने भेज दिया था, तो वहां के प्रबन्धकों ने, वहां के चेयरमैन महोदय ने और भारत सरकार ने इतना धीरज क्यों नहीं रखा कि इस ट्राइब्यूनल का एवार्ड आ जाये और फिर लेबर यूनियन को इस बारे में कहने का कोई मौका न रह जाये। वहां पर जो लेबर यूनियन के नेता हैं, उनका यह कहना है कि जो भी फैसला ट्राइब्यूनल का होता हम उसे स्वीकार कर लेते, लेकिन फैसला होने के पहले ही सरकार ने फिर एक बार प्रोजेक्ट एलाऊन्स को घटा दिया है, जो कि समझ में नहीं आता है। जब कुछ ही दिन पहले वहां के कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ाया

गया था तो एक गलत तरीके से वहां के लोगों का प्रोजेक्ट एलाऊन्स कम कर देना बहुत ही अनुचित बात है। आपने एक हाथ से तो दिया और दूसरे हाथ से उसी चीज़ को वापस ले लिया, तो क्या आप समझते हैं कि इससे वहां के कर्मचारी और लेबर संतुष्ट हो जायेंगे। सरकार और वहां के प्रबन्धकों ने इस संबंध में धीरज क्यों नहीं रखा तथा ट्राइब्यूनल के एवार्ड का इन्तज़ार क्यों नहीं किया। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह बात सच है कि कंसिलिएशन आफिसर और लेबर कमिश्नर, दोनों ने ही इस तरह से प्रोजेक्ट एलाऊन्स को घटाने को अन-वरंटेड और अन-लाफुल कहा था। इसके बाद भी प्रबन्धकों ने इसको कम करने का फैसला किया कि एक अनुचित बात है।

मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी 12 मांगें थीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनकी 12 मांगें नहीं थीं बल्कि 13 मांगें थीं। 12 और 13 में कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इन मांगों में से कुछ मांगें ऐसी हैं जिनमें हमें मानवीय दृष्टि से सोचना चाहिये और साधारण सिद्धान्त तथा डाक्टोरियन सिद्धान्त के आधार पर नहीं सोचना चाहिये। लेकिन मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि वहां पर जो लोएस्ट-पेड वर्कर है, जो डेली एरेटेड वर्कर है, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी जानी चाहियें। यह उनकी एक मांग है और सरकार को इस मांग आने का इन्तज़ार नहीं करना चाहिये था, बल्कि अपने आप ही इसके बारे में प्रबन्ध कर देना चाहिये था।

मुझे यह भी बतलाया गया है कि वहां पर कुछ ऐसे लेबरर्स हैं, कुछ ऐसे श्रमिक हैं जिनकी भूमि में यह विशाल कारखाना बनाया गया है। जो लैण्ड-सफरर्स है, जिनकी भूमि में इतना बड़ा विशाल कारखाना बना है, उन्हें आपने उसी कारखाने में काम पर लगा दिया है, यह आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उन लोगों को अभी तक आप ने परमानेंट नहीं किया है। उनके लिए आपने डेली-रेटेड और डेली-वेजेज़ की पद्धति रखी है और इस तरह से महीने में तीन इतवार का उन्हें वेतन नहीं मिलता है। यह तरीका आपने इस लिए अख्तियार किया है, ताकि वे किसी तरह से भी 90 दिन एक साथ पूरा न कर पायें और फैक्टरी ऐक्ट के मातहत न आ सकें। इस तरह की आपके होशियारी की है जो कि एक अनुचित बात है। सरकार इस तरह का रवैया उन लोगों के साथ, जिनकी उसने भूमि ली है, जो एक तरह से भूमि लिये जाने के कारण निराश्रित हो गये हैं, उनके साथ सरकार इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है; और क्या उनकी एक मांग को सरकार पूरा नहीं कर सकती है?

महोदय, मिनिस्ट्रियल स्टाफ की कुछ मांगें भी हैं।

श्री उपसभापति : आप कितने सवाल एक साथ पूछेंगे?

डा० भाई महावीर : मैं एक मिनट में अपना सवाल खत्म कर दूंगा। मिनिस्ट्रियल स्टाफ से 1962 से 1967 तक साढ़े छः घंटे के हिसाब से काम लिया जाता था और अब उसको बढ़ा कर आठ घंटे कर दिया गया है। यह भी एक असंतोष का कारण है और मैं चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस तरह के परिवर्तन के पहले उन लोगों से, कर्मचारियों से, कोई बात की थी या उसने करना जरूरी नहीं समझा और युनिलेटरली इस तरह का फैसला कर दिया।

प्रमोशन की पालिसी के बारे में भी सरकार का कोई नियत आधार होना चाहिये कि किस हिसाब से प्रमोशन होगा और इस संबंध में भी उनकी एक मांग है। क्या सरकार इस मांग के संबंध में भी उचित कार्यवाही करेगी?

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कारखाने में रोज़ ढाई और पौने तीन लाख

[डा० भाई महावीर]

का उत्पादन होता है और जब हमने यह पूछा था कि अगर प्रोजेक्ट एलाऊन्स कम नहीं किया जाता तो सरकार को कितना कुल खर्चा करना पड़ता, तो इस संबंध में मुझे बतलाया गया कि सरकार को इस संबंध में 10 या 12 लाख रुपया खर्च करना पड़ता। इस तरह से सरकार को वहां के कर्मचारियों को प्रोजेक्ट एलाऊन्स देने में करीब 10 या 12 लाख रुपया देना पड़ता जबकि आज हड़ताल को हुए 5 दिन हो गये हैं और इस तरह से उसे करीब 12 लाख रुपये का नुकसान हो चुका है। आगे जितने दिन भी हड़ताल चलेगी, ढाई लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको नुकसान होता रहेगा, केवल प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर सरकार तथा वहां के प्रबन्धकों ने उनके प्रोजेक्ट एलाऊन्स को कम कर दिया है। महोदय, प्रोजेक्ट एलाऊन्स को कम करते समय सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह 21 दिन का नोटिस कर्मचारियों को इस संबंध में देती। क्या प्रबन्धकों ने लेबरों को इस संबंध में नोटिस दिया था कि फलां दिन से तुम्हारा प्रोजेक्ट एलाऊन्स कम कर दिया जायेगा। ये कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा।

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED: Sir, I have listened with attention to the various questions which have been raised by my hon. friend. I would like to point out that the main dispute at present appears to be with regard to the project allowance. As I have said in my statement before the House, the project allowance is an allowance which was given to the workers of this unit for the purpose of overcoming certain difficulties in regard to amenities and facilities which are obvious during the stage of construction of the project. And I have also pointed out that we have two other units of B.H.E.L. and in those two units also the same policy was followed *i.e.* after the project was completed, the project allowance which was given for lack of facilities like houses, schools, hospitals and so on, was taken away. And in order that the labour may not suffer from any difficulty, it was tapered off from time to time. It is the policy that it should not be withdrawn all at once but gradually. The same policy is being pursued in this unit also.

Now the hon. Member has raised the question why no notice of such withdrawal was given. May I point out that these allowances are not part of the substantive wages which are given to the workers? These are allowances which are considered and decided at the Board's meeting and are given from one period to another period. Now the allowance which was given in the year 1969 ended on the 31st March, 1970. And if no decision had been taken, then after that date they would not have been entitled to any allowance. Therefore, the decision was legal for the Board to take and no notice for that purpose was necessary. They wanted to decide what would be allowance given for the year 1970. Therefore, the Board met in April, 1970 and decided that it should be further reduced according to policy which has been laid down. So, I submit that for the purpose of withdrawing the project allowance no notice is necessary because it is only for a certain specified period that the allowance is given and the Board had to take a decision as to what will be its attitude for giving the project allowance for the next year, *i.e.* 1970-71; therefore, the decision was taken in April, 1970.

May I also submit that so far as this particular dispute is concerned, it is not before any conciliation proceedings. There was the other matter which was referred to conciliation proceedings and as far as my information goes, the Labour Commissioner of U.P. reported failure of the conciliation in the earlier case of reduction from 20 per cent to 15 per cent, but held that the order of the management to reduce the project allowance was within the management's competence. So far as the present question is concerned, it is now under consideration. I would appeal to the hon. Members to help me in creating an atmosphere so that the matter may be settled suitably between the labour and the management. In fact, Mr. Pande the other day saw my Secretary and also the Chairman of the B.H.E.L. and they discussed the matter across the table with the labour and management, and for that purpose a letter was also obtained. They said that if the letter is given they will try to persuade the labour to come and discuss the matter and settle the matter. It was expected that as a result of this letter the strike will be withdrawn, but till now it has not been withdrawn. I would appeal to the House

that we should not say or do something which is likely to deteriorate the situations Our management is prepared to discuss not only this demand but also other demands across the table, and, if necessary we can refer the matter to adjudication.

DR. BHAI MAHAVIR : One point has been completely missed. The hon. Minister has been at pains to tell us that the project allowance is given during the interim period when certain facilities are not there. I would like to know. Is it not a fact that the project allowance was withdrawn at Tiruchy after practically residential accommodation had been provided to all workmen? There, I learn, free electricity is provided, twelve units of electricity are provided to every individual workman But here electricity is sold at exorbitant profit and only 30% of the people have been provided with residential accommodation. Now, if at Tiruchy these facilities have been provided, what stands in their way here? You can appeal all right. I may assure the hon. Minister that I find these labour leaders . . .

MR. CHAIRMAN : No question of assurance.

DR. BHAI MAHAVIR : If the Government stands on prestige unnecessarily, it will not help the situation.

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : I may just point out that it is not correct to say that in other units this project allowance was withdrawn after houses to all the labourers were provided.

DR. BHAI MAHAVIR : Lump sum was given.

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : May I just say that there also the position is the same. It is our effort to provide housing facilities to the labour, as far as possible. But it has not been possible for us to provide accommodation for every labourer in the unit. May I just say that so far as Tiruchy is concerned, the number of workmen there is 5,813 and the number of quarters provided there is 2,328, that is, nearly 40 per cent. So far as Hyderabad is concerned, the number of workmen there is 5,022 and the number of quarters provided is 2,307, that is, 46 per cent. So far as Hardwar is concerned, the number of workmen is 4,970 and the number of quarters provided is 2,297, that is, also 46 per cent. So, in any case, Hardwar is not in a worse position than other units. And may I also say that when this project allowance is withdrawn, those workers who are not provided with a house, they are given a house rent allowance. They are given a house rent allowance therefore, it cannot be said that there is any discrimination between one set of labourers and the others.

DR. BHAI MAHAVIR : Why don't you advise the Chairman to go there? Let him go there.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (राजस्थान) : आपने सुविधाओं की बात कही। आपने जो रिपोर्ट सर्कुलेट की उससे भी लगता है कि जितना रुपया आप खर्च करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट में, 89.22 करोड़ रुपया खर्च करना चाहते हैं, उसमें से केवल 73.48 करोड़ रुपया आप खर्च कर पाए। जो बाकी रुपया आप खर्च नहीं कर पाए उसमें मुख्यत: वह रुपया है, जो श्रमिकों को सुविधाएं देने पर खर्च होने वाला था, वह रुपया आप अभी तक खर्च नहीं कर पाए। दूसरे, यह प्रोजेक्ट जो रशियन एसिस्टेंस से आप बना रहे हैं डिवैल्युएशन के कारण आपको लगभग 2.7 करोड़ रुपया ज्यादा देना पड़ा। इसके अलावा आप आज लासेज़ इनकर कर रहे हैं, आपका लेटेस्ट लास पिछले साल का है 401.80 लाख। डिवैल्यूएशन के कारण आपको ज्यादा रुपया देना पड़ा और श्रमिकों को फेसिलिटीज़ देने पर जो रुपया खर्च करना था वह आप खर्च नहीं कर पाए। जो फारेन एसिस्टेंस आनी चाहिए थी, शायद वह नहीं आई, आपको रुपया बाकी पड़ा है और यह प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ, प्रोजेक्ट अधूरा है और जब प्रोजेक्ट अधूरा है और उसके पूरा होने के पहले ही आप श्रमिकों से यह कटौती कर रहे हैं। प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो उसके बाद जो फेसिलिटी एक श्रमिक को देनी चाहिए थी उतनी देते, उसके बाद नियमानुसार कटौती करते, तो कोई आपत्ति नहीं होती। प्रोजेक्ट के पूरे हुए बिना ही आपने ऐसी कटौती शुरू कर दी। क्या इसका अर्थ यह नहीं होगा जो प्रोजेक्ट अभी भी लास में जा रहा है, श्रमिकों को और नाराज़ करके,

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]
उनको परेशान करके यह नेशनल प्रोजेक्ट फिर घाटे में जायेगा ? हमारा प्रोजेक्ट घाटे में न जाये और श्रमिक संतुष्ट रहें इस नाते से जो लेबर ने एतराज किया है कि कानपुर के अन्दर हमारी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स थीं उसके पहले ही और जो एडवाइस कानपुर के लेबर कमिश्नर ने दी उसको हीड किए बिना ही आपने कटौती कर दी, उस दृष्टि से क्या आप इस समस्या पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं या नहीं ?

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : Sir, as I have already pointed out, the construction work, out of which they were likely to get amenities and facilities, is practically over. It is true that houses for all of them have not been provided. We have a phased programme to undertake the construction of houses for the remaining workers also. But for that purpose, such people who are not provided with a house, will be given some house rent allowance. I think the house rent allowance is at the rate of $7\frac{1}{2}$ per cent or 10 per cent; I am not sure about the percentage. But this allowance is given to such people who are not provided with a quarter.

Now, so far as the remaining expenditure which has to be incurred in this project is concerned, it is not only for the purpose of providing amenities to the workers but for completing other works also. At present, I have not the details what was the project and how it has increased. If I get notice, I shall be able to give the details.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : एमिनिटीज कितनी पूरी नहीं हुईं, यह तो बता सकते हैं।

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : That is what I have said. So far as the hospital is concerned, so far as quarters are concerned, provision of electricity is concerned, they are almost complete, except in the matter of providing houses. Houses for the entire labour have not been provided. And this is the position not only in this unit but in many other units also.

श्री ना० कृ० शेजवलकर (मध्य प्रदेश) : माननीय मंत्री जी क्या यह बताएंगे कि जो वेतन बढ़ाया गया था वह कितना बढ़ाया गया था और किस समय बढ़ाया गया था ? उस समय क्या इस बात पर विचार किया गया था कि प्रोजेक्ट एलाऊन्स कम होने वाला है। टेक्नीकल प्रश्न तो यह उपस्थित किया जाता है कि वह स्ट्राइक लीगल नहीं है और दूसरी तरफ स्वयं यह बात कही जाती है कि प्रोजेक्ट एलाऊन्स तब कम किया जायेगा जब कार्य पूरा हो जायेगा। अभी कार्य पूरा हुआ नहीं है। क्या मैं यह समझूं कि अभी भी शासन टेक्नीकल आपत्तियों को छोड़कर, इसको प्रेस्टिज का सवाल न बनाते हुए ह्यूमेनीटेरियल प्वाइन्ट आफ व्यू से चेयरमैन को कर्मचारियों की यूनियन से और एम्पलाइज़ से बात करने के लिए भेजेगा, ताकि एक टेबल पर बैठ कर इसके सम्बन्ध में विचार हो सके जिससे यह जो राष्ट्रीय हानि हो रही है, वह राष्ट्रीय हानि जल्दी से जल्दी समाप्त हो ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो प्रश्न अभी प्रस्तुत किये गये थे और जो तमाम उनकी मांगें थीं उसमें भी अनेक महत्वपूर्ण मांगें हैं, केवल प्रोजेक्ट एलाऊन्स के बारे में ही कुछ कर देने से काम नहीं चलेगा। उदाहरण के लिए मिनिस्टिरियल स्टाफ के कार्यकाल में जो वृद्धि की गयी है 6 घंटे से 8 घंटे की और शनिवार का जो उनको लाभ मिलता था, सेकिंड सेटरडे का, उसके लिए जो कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है उसके बारे में जो असंतोष है उसके लिए शासन ने क्या विचार किया है और वह क्या निर्णय करना चाहता है ? मेरी समझ में यह नहीं आता है कि जो प्रतिवेदन आप के पास उन्होंने भेजा है उसमें उन्होंने यह स्पष्ट लिखा है कि हम कंसीलियेशन के लिए तैयार हैं, हम आर्बिट्रेशन के लिए तैयार हैं, इस की लीगेलिटी को देखा जाये कि कितनी रकम निर्धारित की जानी चाहिए और वे आर्बिट्रेशन को मानने के लिए तैयार हैं तो फिर आप इसको प्रेस्टिज का सवाल क्यों बनाये हुए हैं। जैसा आंकड़ों से पता लगा कि ढाई लाख रुपये की प्रत्येक दिन हानि हो रही है और इस स्ट्राइक को चलते कितने ही दिन हो गये हैं और इस से पता चल सकता है कि

हमारी कितनी हानि हो चुकी है और इसके साथ ही जो बाकी व ा फैसिलिटीज हैं, हाऊस एलाऊन्स के साथ । कैसे मेल खाती है यह मेरी समझ में नहीं आता है . . .

श्री नेकी राम (हरियाणा) : जब समझ में नही आता, तो पूछते क्यों हो ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह खेती का सवाल नही है, मजदूरी का मामला है।

श्री ना० कृ० शेजवलकर : मै यह पूछना चाहता था कि जब आप कह रहे है कि हम हाऊस एलाऊन्स साढ़े सात परसेंट दे रहे हैं तो यह कैसे कंपेंसेट किया जा सकता है, यह विचार करने वाली बात है। जब आप 15 परसेंट प्रोजेक्ट एलाऊन्स देंगे, 20 परसेंट तक और हाऊस एलाऊन्स के रूप में 7 या 8 परसेंट देंगे तो उनकी कमी को कैसे पूरा किया जायेगा ? इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इन सब बातों पर पुर्नविचार शासन को करना चाहिए। क्या शासन इसके लिए तैयार है और अपने चेयरमैन को भेज कर उनसे बात करने के लिए शासन तैयार है क्या ?

श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद : मैंने पहले ही कई बातों का जवाब दे दिया है और हम यह चाहते हैं कि जो भी बातें हों वह लेबर में और हमारे मैनेजमेंट के बीच में हों, वे मिल कर बात करे और इसके लिए हमने एक खत भी उनको लिख दिया है। हमसे कहा गया था कि अगर कोई खत दिया जायेगा तो उसकी बिना पर लेबर को समझाया जायेगा कि वे यहां दिल्ली में आ कर हमारे अफसरों के साथ और मैनेजमेंट के साथ बैठ कर तमाम बातें करें।

श्री ना० कृ० शेजवलकर : मै इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप भेजेंगे, आप उनको बुलायेंगे, इस सब में समय लग सकता है, क्या यह बात अच्छी नही है कि इस मामले को जल्द सुलझाने के लिए आप अपने ही किसी आदमी को वहां भेजे या किसी अधिकारी को भेजें ताकि वहीं पर मामला जल्दी से निपट जाये। वह लोग यहां आयें और कोई निर्णय हो इसमें समय लगेगा और हमारा नुकसान रोज़ हो रहा है।

श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद : वहां के एक लेबर लीडर हैं पांडे साहब, जो मेम्बर पार्लियामेंट भी हैं। वह रिकग्नाइज्ड यूनियन के हैं। उन्हीं से तमाम बातें हुई हैं और उन्होंने कहा कि हम उनको समझायेंगे और उनको यहां ले आयेंगे। जहां तक इन्क्रीज का ताल्लुक है, अभी नवम्बर, 1969 में जो मज़दूरी में इंक्रीज़ हुआ है, उसके हिसाब से लोएस्ट पेड मज़दूर को 41.10 रुपये तनख्वाह में बढ़े हैं। बाकी औरों की तनख्वाह में भी इसी तरह से बढ़ती हुई है। उसके आंकड़े मेरे पास यहां नहीं हैं। हम तो यही चाहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द फैसला हो जाये और मैं गवर्नमेंट की तरफ से कहना चाहता हूं कि अगर यह मामला मैनेजमेंट और लेबर के बीच तय नहीं हो जाता, तो हम इसको एडजुडिकेशन के लिए भेजने को तैयार हैं।

श्री श्रीकान्त मिश्र (बिहार) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया कि जिसके कारण आप जो प्रोजेक्ट एलाऊन्स दिया करते थे उसे बंद कर रहे हैं ? अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट का वर्क कितने परसेंट कंप्लीट हो गया और कितना बाकी है। अगर आपको प्रोजेक्ट एलाऊन्स में कमी करनी थी तो उतने ही परसेंट वर्कर्स को एफेक्ट करना था जितने परसेंट कि प्रोजेक्ट का काम पूरा हो चुका है, ऐसा न करके आपने सारे वर्कर्स को एफेक्ट कर दिया है, यह क्यों? आपने यह भी बताया कि आपने 46 परसेंट को आवास दिया है और हैदराबाद से इसकी तुलना की कि वहां भी आपने 46 परसेंट को आवास दिया है और बाकी को आवास नहीं मिला है, लेकिन बाकी का प्रोजेक्ट एलाऊन्स कैंसिल कर दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हैदराबाद में इसके कारण कोई स्ट्राइक

[श्री श्रीकान्त मिश्र]

नहीं हुआ, इस बात पर मजदूरों ने कोई स्टेप नहीं लिया तो क्या यह एक्जाम्पुल बाकी के सारे प्रोजेक्ट के लिए भी रहेगी ? मेरा ख्याल है कि जितने परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है उतने परसेंट लोगों को ही आप वहां एफेक्ट करते तो आज यह स्थिति न होती और इतनी राष्ट्रीय क्षति न होती । तो मैं इन बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : मैंने इस बात का भी जवाब दिया था । प्रोजेक्ट एलाउन्स बहुत सारी एमीनिटीज का ख्याल रख कर दिया जाता है । वहां उनके लिए घर बनें, उनके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो, अस्पताल खोले जायें, क्लब्स हों, इन सबसे उसका ताल्लुक है । घरों के अलावा और जितनी एमीनिटीज हैं वह सब करीब करीब इस प्रोजेक्ट में मुहैया हैं इसलिए उनके लिए इस एलाउन्स की जरूरत नहीं, लेकिन बाकी तमाम वर्कर्स को जो घर नहीं दिये गये हैं इसका ख्याल रख कर हम प्रोजेक्ट एलाउन्स प्रपोर्शनेटली आहिस्ते आहिस्ते काट रहे हैं और उन लोगों को जिनके पास घर नहीं हैं और जो इस प्रोजेक्ट से बहार रहते हैं उनका जब यह प्रोजेक्ट एलाउन्स काटा जायगा तो उनको हाउस एलाउन्स दिया जायगा ताकि किन्हीं दो वर्कर्स में डिस्क्रिमिनेशन न हो । इसलिए हाउस एलाउन्स से प्रोजेक्ट एलाउन्स का कोई ताल्लुक नहीं है । और यह तो हमेशा होता है । किसी प्रोजेक्ट में हम तमाम वर्कर्स को एक ही वक्त में या चन्द बरस के अंदर घर नहीं दे सकते । आहिस्ते आहिस्ते उन लोगों के लिए घर बनते जाते हैं और उनको घर देते जाते हैं । प्रोजेक्ट एलाउन्स तो एमीनिटीज हो जाने के बाद खत्म होने की जरूरत है ।

SHRI KALYAN ROY (West Bengal) : Sir, I suppose the hon. Minister will agree with me that the Soviet Union cared to develop first the basic industries while in this country we are denied the development of the basic industries because of the American power, particularly in the public sector. Unfortunately for the last six months or so we find that in these public sector projects there are certain officers who are taking more and more an extremely anti-labour view resulting in the complete stoppage of production as, for example, in Hardwar or in the Neyveli Lignite Corporation. And in the Madras Dockyard the strike is still continuing. Would the Minister agree that there are certain officers in the Hardwar plant who are deliberately provoking the workers by denying them the most legitimate demands which have been put forward by the three unions ? This is the first aspect. My second question is this. Is it not a fact that the HMS Union, the AITUC and the third independent union which is led by Jan Sangh, had made it clear that you should not sign any agreement with the INTUC which is split into two, the Syndicate group and the Indicate group? Is it also not a fact that this particular management against the request of all the unions, came to an agreement with a union which is a minority union led by the Syndicate group? Is it also not a fact that this particular officer or the management which is in league with the Syndicate group, in order to sabotage the Hardwar plant, saw to it that the strike continued? Lastly, it is true that some wage rise has been given. But, though this wage rise may sound or look big on paper, actually when the workers calculate the amount and take their pay packet, they find that it has been slashed down by half because of the arbitrary and unjustified denial of this particular project allowance which they were getting. So now, would he consider merging this project allowance with the wages and would he also consider consulting all the unions instead of discriminating against them in favour of a particular union led by the Syndicate? I also want a reply about the particular officer who is sabotaging the Hardwar plant.

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : It is true that today the management is faced with the difficulty of negotiation so far as the unions are concerned; not only in this project, but in many other projects there is more than one unit. And so far the policy pursued is that the management generally holds its talks with the office-bearers of the union which is recognised . . .

SHRI KALYAN ROY: What is the basis of recognition?

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : May I just say that so far as my information goes, there are about 4,970 employees in this project of whom the number of members of the recognised union is 2,534? And this was verified by the State Labour Department in 1969. Therefore, the management has no other option but to negotiate with this recognised union, the number of which has also been verified. But in this union there is also the AITUC and there is also the unregistered Jan Sangh union and there is also the unregistered HMS union.

SHRI KALYAN ROY : They opposed it.

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : They opposed it. Therefore I have offered not only here but in other places also that it would be better if all the workers in a particular unit are registered and through their vote they should decide which management they will constitute so that negotiations can be carried on with that management. If that is done, that will be better both for the labour as well as for the management. The hon. Member need have no apprehension and I can assure him that I would not allow anything which will stand in the way of the development of public undertakings or that any officer will do something which will harm these undertakings.

SHRI MAHITOSH PURAKAYASTHA (Assam) : Mr. Deputy Chairman, from the replies given by the Minister it seems that the Government is prepared to consider the legitimate demands of the workers but it seems that because of the multiplicity of these unions the strike was hastily resorted to. So, will the Minister be pleased to accord recognition to only that union which enjoys the majority support of the workers?

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : This procedure has been adopted and this was verified by the State Labour Department in December 1969 and therefore we have given recognition... (*Interruption*) At present we have no material to say which portion is Indicate and which is Syndicate but it is the INTUC.

SHRI A. D. MANI : I am sure the hon. Minister will agree that there should be no strike in the public sector undertakings. The hon. Minister mentioned that the Board of Management has decided to withdraw the project allowance. I would like to ask him whether he gave notice of this change to the unions concerned. This is the procedure followed under the Industrial Disputes Act. If it is not done in a private industry, that private employer will be hauled up for infringing the provisions of the Act. Of course there may be adequate grounds for withdrawing the project allowance. Now, Sir, he has also mentioned that he is prepared to refer the matter for adjudication. We do not want the strike in this undertaking to continue for a long time. What has been the reaction of the Minister of Labour to the suggestion made by the Minister that the entire matter should be sent for adjudication? We want peace to be restored in this undertaking so that the tax payer's money is not wasted due to these losses.

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : Sir, so far as the latter part of the question is concerned, the Deputy Labour Commissioner of U.P. is being associated in order to bring about a settlement of this dispute. Now so far as the notice is concerned, I have already pointed out that no notice is necessary so far as the project allowance is concerned because this allowance is given for a specified period from time to time and when that period expires, it is automatically stopped after the end of the financial year. But in order that there may not be any further difficulties to the workers, a further reduction has been announced for the next year.

SHRI D. THENGARI (Uttar Pradesh): Sir, obviously the hon. Minister has been misinformed by the local management on certain points. I would not go into all the details. But the Bharatiya Mazdoor Sangh Union is not unregistered as suggested by him. Also the procedure of progressive reduction in the project allowance as followed in Tiruchi was not followed at Hardwar. You may enquire about it. And it is certainly a violation of section 4(1) of the Industrial Disputes Act. Now in view of the fact that the Government is in a mood to settle the dispute, may I ask whether the Government will assure that there will be no victimisation as a result of the strike action? Secondly, the talks should be conducted at Hardwar itself because in that case the local labour leaders will be in a position to be in communion with their co-workers. Thirdly, because it is not possible for the local management and the local labour leaders to arrive at any agreement because of the strained relations, will any special officer be sent for this purpose so that he can bring about such a settlement?

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : Sir, so far as the three points are concerned, I would accept the suggestion of sending an officer from here and also I I will see that the matter is discussed there at the local level. But as regards details, I think it will be better that we should not discuss those details here.

SHRI D. THENGARI : With a view to creating a congenial atmosphere, Sir, there should be no victimisation.

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : This is also a point which will be discussed there.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal) : Sir, the hon. Minister has taken a very technical view of the problem as to whether the withdrawal of the project allowance which was being given to the workmen is justified and he said that according to the advice given by the Uttar Pradesh Labour Commissioner it is justified. This is a very technical approach which the hon. Minister has taken. He has also taken another view that some other unit of this has also given effect to the withdrawal of the project allowance which was earlier being given to them. Therefore he wanted to make it on a par. In this context, Sir, may I know whether they have also taken into consideration the proportion of amenities being extended and the proportion of the reduction of the project allowance? I also want to take a technical view in this matter, Sir. Wages are fixed on the basis of different regions, not on a national basis. It cannot be taken for granted that the wage scale in Hardwar should be given in other regions also, because wages are fixed on the basis of the cost of living index in a particular region. Therefore, may I know whether the Government, if it is interested in bringing about an amicable settlement, will consider the proposal of my friend, Mr. Kalyan Roy, to merge the project allowance with the wage itself in view of the cost of living index that is prevailing in the country today?

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : Sir, so far as the rise in wages is concerned, I have already pointed out that after taking into consideration the various factors only in November 1969 the lowest worker was given a rise of Rs. 41.10.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN (Kerala) : Mr. Deputy Chairman, Sir this raises according to me larger issues than the one merely involved in the strike: I would particularly impress on the hon. Minister for Industrial Development that the entire programme of industrial development in the public sector in this country is likely to be torpedoed unless Government takes the clear warning on the sky. It is sad and lamentable that employer-employee relations in most of our public sector concerns are bad enough and are worse than the employer-employee relations that exist today in some of the primary and more important of the private sector concerns of this country. The faith of the people in the public sector itself is being lost . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You should ask question regarding the strike in Bihar.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN : I am coming, Sir, I am giving the background. And if that faith is lost, certainly the entire programme of investment in the public sector would be defeated. May I know from the hon. Minister as to how far the Chairman or the Managing Director of this big industrial concern at Hardwar in the public sector is responsible for the present state of affairs in the factory? May I know from the hon. Minister whether he would review the entire position of management and personnel in this public sector concern and in other public sector concerns so that more and more of non-official members and public men would be appointed to top posts of management in our public sector concerns in preference to the officialdom and the bureaucrats?

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : I have no material with me to come to the view that anything which is not in the interests of the unit has been done by the Chairman. I find that he is one of our efficient persons who has been conducting the work very efficiently and unless and until I have something concrete with me I cannot come to that conclusion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Rajnarain, last question.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या फैक्ट्री एक्ट यहां लागू है या नहीं, इंडस्ट्रियल डिसप्यूट एक्ट के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं। एक अजीबोगरीब तर्क माननीय मंत्री जी के मुंह से सुनना पड़ा कि इनकी स्वीटविल पर है यह जब चाहे तब प्रोजेक्ट एलाउंस दें और

जब चाहे तब छीन लें। दुनिया में यह ही एक मंत्री हैं जिनके मुंह से हमने यह बात सुनी है कि जब चाहें तब दें और जब चाहें तब छीन लें। यह प्रोजेक्ट एलाउंस एक ग्रेचुएटी होती है और लेबर डिस्प्यूट में कितने फैसले ऐसे हैं जो कि ग्रेचुएटी को हर्गिज छिनने नहीं देते। तो जब यह मामला विचाराधीन था उत्तर प्रदेश के लेबर कमिशनर ने क्या लिखा और क्या नहीं लिखा इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेबर कमिश्नर तो केवल नाम है लेकिन वह ओनर कमिश्नर है, वह मालिकों के हित-रक्षक हैं, मजदूरों के हित-रक्षक नहीं, तो जब यह मामला झगड़े में था तब कांसिलियेशन के सामने कौन कौन से प्वाइंटस थे और जब वे प्वाइंटस विचाराधीन थे तो उसके बीच में एक प्रोवोक करने के लिये यकायक लेबर का यह एलाउंस क्यो छीना गया।

श्रीमन, क्या सरकार इस बात को जानती है कि वहां का जो लेबर है वह शान्त है, काम करना चाहता है, मगर वहां का जो मैनेजमेंट है वह स्वतः नौकरशाह है। आजकल का जो पबलिक सेक्टर है, इसके चाहें डाइरेक्टर हों चाहें मैनेजर हो, वह अपने को इतना बड़ा समझे हुये हैं कि लेबर से घृणा करते हैं, लेबर उनके पास जाता है तो उनको आने नहीं देते।

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछ लीजिये।

श्री राजनारायण क्या सरकार के पास यह जानकारी आई है। तो ये सारी की सारी अव्यवस्थायें हैं और इस समय वहां के कारखाने का जो नुकसान हुआ है, जनता के धन का नुकसान हुआ है और वह नुकसान हुआ है वहा के मैनेजमेंट के गलत, एंटी-लेबर रुख के कारण और उत्तर प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल डिसप्यूट एक्ट है उसके विरुद्ध आचरण करनें के कारण। तो सारे का सारा नुकसान क्या सरकार उनसे लेगी जो कि वहां के मैनेजमेंट में हैं। मैं इतनी बात जानना चाहता हूं।

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : I have already said about all these matters. I would like to state here once again that we should not sit in judgment here as to who is right or who is wrong.

श्री राजनारायण : श्रीमन, मेरा सवाल यह था कि कांसिलियेशन के सामने कौन कौन प्वाइंटस थे।

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : I have already made an offer that in order to see who is right, who is wrong, the whole matter may be sent for adjudication but let good feelings be shown from all sides and I am prepared to send my officer to discuss the matters. Let the labour also in the interests of the unit call off the strike and after that they can sit and discuss. And whatever matters they cannot settle among themselves, those matters can be referred to adjudication.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, जरा सुना जाय। उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डिसप्यूट एक्ट के मुताबिक यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब चाहेगी तब वह मामला एडजुडिकेशन में देगी, श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद के चाहने से नहीं। श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद सदन में कुछ कह दें कि मामला एडजुडिकेशन में जायगा, हम चाहते हैं तो भी वह नहीं चला जायगा।

श्री उपसभापति : आपका सवाल भी स्पष्ट हो गया और जवाब भी आ गया। अब आप बैठिये।

श्री राजनारायण : तो मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जो यह कह रहे हैं कि मामला एडजुडिकेशन को सौंपा जायगा इसकी गारंटी क्या है, क्या मंत्री जी के पास कोई ताकत है कि जो मंत्री जी यहां पर आज गारंटी दे सकें कि सारा का सारा मामला एडजुडिकेशन में जायगा यह मालूम करने को कि मजदूरों का अपराध है या मालिकों का अपराध है। सीधी बात है कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट एलाउंस को छीना यह कानून की निगाह में जबरदस्त अपराध है और इसके सम्बन्ध में यह सरकार क्या कर रही है?

SHRI FAKHRUDDIN ALI AHMED : I have already replied to all these.

श्री राजनारायण : मैं तो खुद ही वहां जाने वाला हूं। इतवार को मैं मथुरा के चुनाव से खाली होऊंगा तो हरिद्वार जाऊंगा।

SHRI D. THENGARI : In order to create a congenial atmosphere for bringing about a settlement I would urge the Government not to stand on prestige. It is common decency that the Government should assure that there shall be no victimisation. Then only the atmosphere will be congenial.

DR. BHAI MAHAVIR : That is the very minimum they can say.

PAPERS LAID ON THE TABLE

THE REGISTRATION OF NEWSPAPERS (CENTRAL) AMENDMENT RULES, 1970

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (PROF. SHER SINGH) : Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (2) of section 20A of the Press and Registration of Books Act, 1867, a copy of the Ministry of Information and Broadcasting Notification G.S.R. No. 203, dated the 20th January, 1970 (in English and Hindi), publishing the Registration of Newspapers (Central) Amendment Rules, 1970. [Placed in Liabrary. *See* No. LT-3154/70]

PAPERS UNDER THE COMPANIES ACT, 1956

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHEB SHINDE) : Sir, I beg to lay on the Table, a copy each of the following papers, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 (in English and Hindi):—

(i) Annual Report and Accounts of the National Seeds Corporation Limited, New Delhi, for the year 1968-69 together with the Auditors' Report on the Accounts.

(ii) Review by Government on the working of the Corporation.

[Placed in Library. *See* No. LT-3501/70 for (i) and (ii)]

NOTIFICATIONS UNDER THE ESSENTIAL COMMODITIES ACT, 1955

SHRI ANNASAHEB SHINDE : Sir, I also beg to lay on the Table, a copy each of the following Notifications of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Food), under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (in English and Hindi):—

(i) Notification G.S.R. No. 427, dated the 10th March, 1970, publishing the Tripura Foodgrains Movement Control (No. 2) Amendment Order, 1970. [Placed in Library. *See* No. LT-3564/70]

(ii) Notification G.S.R. No. 664/Ess. Com./Sugar, dated the 23rd April, 1970, publishing the Sugar (Price Determination) Third Amendment Order, 1970. [Placed in Library. *See* No. LT-3565/70]

ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1968-69) OF THE INDIAN TELEPHONE INDUSTRIES LIMITED, BANGALORE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (PROF. SHER SINGH) : Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956, a copy (in English and Hindi) of the Nineteenth Annual Report and Accounts of the Indian Telephone Industries Limited, Bangalore, for the year 1968-69, together with the Auditors' Report on the Accounts. [Placed in Library. *See* No. LT-3504/70]

REPORT OF THE INDIAN GOVERNMENT DELEGATION TO THE 53RD SESSION OF I.L.O.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI S. C. JAMIR) : Sir, I beg to lay on the Table, a copy of the Report of the Indian Government Delegation to the 53rd Session of the International Labour Conference held at Geneva in June, 1969. [Placed in Library. *See* No. LT-3507/70]